

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 41/2023(GCMS : 2023/ 56)

ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में ए यू फाईनेंसर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) शाखा कार्यालय 4-ई-8 जवाहर नगर, प्रथम तल, मीरा चौक रोड, नजदीक गौड़ हॉस्पिटल, श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता - पोर्टफोलियो कलैक्शन मैनेजर मनोज कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद

बनाम

1. दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री विजय कुमार, 40 मुख्य विलेज, 7-एस, सैकण्ड, जिला श्रीगंगानगर पिन कोड-335073
2. सोनिका शर्मा पत्नी श्री दिनेश कुमार शर्मा, निवासी 7 जैड, जिला श्रीगंगानगर पिन कोड-335001
3. करमजीत सिंह पुत्र श्री जोगा सिंह निवासी 205, 7 जैड, जिला श्रीगंगानगर पिन कोड-335001

07.12.2023



पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री राजीव मेहन्दीरत्ता ने एक प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण दिनेश कुमार शर्मा, सोनिका शर्मा एवं करमजीत सिंह को सुविधा के रूप में राशि 7.00/- लाख रुपये (अखरे रुपये सात लाख मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 09.01.2016 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी दिनेश कुमार शर्मा द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 27, किला नं. 12, 19(क्षेत्रफल 1125 सक्वायर फुट), चक 7 जैड, श्रीगंगानगर (वर्तमान प्लॉट नं. 9, गली नं.3, जम्शेश्वर कॉलोनी, 7 जैड, श्रीगंगानगर), का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण दिनेश कुमार शर्मा, सोनिका शर्मा एवं करमजीत सिंह ऋण सुविधा के रूप में 7.00/-लाख रुपये (अखरे रुपये सात लाख) के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 08.01.2016 (पत्रावली में उपलब्ध ऋण स्वीकृति पत्र के

*Am*  
जिला मजिस्ट्रेट  
श्री गंगानगर


अनुसार) प्रदान की थी, जबकि प्रार्थना पत्र में स्वीकृति दिनांक 09.01.2016 को अंकित है। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी दिनेश कुमार शर्मा द्वारा सुरक्षा की एवज में अपनी सम्पत्ति पट्टा नं. 27, किला नं. 12, 19(क्षेत्रफल 1125 सक्वायर फुट), चक 7 जैड, श्रीगंगानगर (वर्तमान प्लॉट नं. 9, गली नं.3, जम्मेश्वर कॉलोनी, 7 जैड, श्रीगंगानगर), प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 08.10.2022 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 10.10.2022 को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 12.10.2022 को भिजवाये गये है, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप ऑनलाईन ट्रैक/प्राप्ति रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी दिनेश कुमार शर्मा की दृष्टि बंधक रखी गई सम्पत्ति पट्टा नं. 27, किला नं. 12, 19(क्षेत्रफल 1125 सक्वायर फुट), चक 7 जैड, श्रीगंगानगर (वर्तमान प्लॉट नं. 9, गली नं.3, जम्मेश्वर कॉलोनी, 7 जैड, श्रीगंगानगर), जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

**जिला मजिस्ट्रेट**  
**श्री गंगानगर**

जहां तक अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 10.10.2022 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 10.10.2022 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण दिनेश कुमार शर्मा, सोनिका शर्मा एवं करमजीत सिंह को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 12.10.2023 भिजवाये गये हैं, धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की पोस्ट ऑफिस की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति परिणामस्वरूप समस्त पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक/प्राप्ति रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जिसके अनुसार समस्त अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हुई है अथवा नहीं? का पता नहीं चलता है और प्रार्थी बैंक ने 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस जारी किया था और पत्रावली में नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप कोई दस्तावेज पेश नहीं किया और 60 दिन पूर्व की धारा 13(2) का नोटिस किसी एक अप्रार्थी की सम्पत्ति पर दिनांक 18.10.2022 को चस्पा कर दिनांक 21.10.2022 को दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया है। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) का 60 दिवस का नोटिस जारी करने पर यदि अप्रार्थीगण ऋणियों पर नोटिस की तामील नहीं होती है और अप्रार्थीगण नोटिस की तामील से बचने का प्रयास करते हैं, तो नोटिस की प्रति उनके निवास स्थान पर चस्पा कर दो समाचार पत्रों में धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन करवाना आवश्यक होता है परन्तु प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) का नोटिस की रिपोर्ट प्राप्त होने से पूर्व ही धारा 13(2) का नोटिस चस्पा कर दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया है

  
**जिला मजिस्ट्रेट**  
**श्री भंमानगर**

नोटिस तामील के सम्बन्ध में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 3 निम्नानुसार अवलोकनीय है:

**Demand Notice**

The service of demand notice as referred to in sub-section (2) of section 13 of the Ordinance shall be made by delivering or transmitting at the place where the borrower or his agent, empowered to accept the notice or documents on behalf of the borrower, actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain, by registered post with acknowledgement due, addressed to the borrower or his agent empowered to accept the service or by Speed Post or by courier or by any other means of transmission of documents like fax message or electronic mail service:

**PROVIDED** that where authorised officer has reason to believe that **the borrower or his agent is avoiding the service of the notice or that for any other reason, the service cannot be made as aforesaid, the service shall be effected by affixing a copy of the demand notice on the the outer door or some other conspicuous part of the house or building in which the borrower or his agent ordinarily resides or carries on business or personally works for gain and also by publishing the contents of the demand notice in two leading newspaper, one in vernacular language, having sufficient circulation in that locality.**

(2) Where the borrower is a body corporate the demand notice shall be served on the registered office or any of the brances of such body corporate as specified under sub rule(a)

(3) Any other notice in writing to be served on the borrower or his agent by authorised officer, shall be served in the same manner as provided in this rule.

(4) Where there are more than one borrower the demand noice shall be served on each borrower.

चूंकि प्रार्थीगण धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 10.10.2022 को जारी कर रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 12.10.2022 को भिजवाया है जिसकी समस्त अप्रार्थीगण को तामील होने के परिणामस्वरूप ऑनलाईन ट्रैक/प्राप्ति रसीद पेश नहीं की, जबकि प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में रजिस्टर्ड डाक से तामील होना बताया है। पत्रावली में तीनों अप्रार्थीगण के निवास का स्थान अलग-अलग अंकित

*Amu*  
जिला मजिस्ट्रेट  
श्री बंमानगर

कर, प्रार्थी बैंक ने एक अप्रार्थी की सम्पत्ति पर धारा 13(2) का नोटिस चस्पा कर दिनांक 21.10.2022 को दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया है, जो THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 के RULE 3(4) के प्रावधानों की अवहेलना है। इस प्रकार समस्त अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की विधिवत् तामील होना नहीं माना जा सकता।

माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीड ने 2012 Cr. I.R.(SC) 726 - State of Bihar & Anr versus Arvind Kumar & Anr के पैरा-13 में भी निम्न प्रकार से निर्देश दिये है :

13. In Manish Goel Vs Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099, this Court has held that generally, no Court has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provisions. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [see also : Vice Chancellor, University of Allahabad & Ors. Vs Dr. Anand Prakash Mishra & Ors., (1997) 10 SCC 264; and Karnataka State Road Transport Corporation Vs Ashrafulla Khan & Ors, AIR 2002 SC 629]

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 में प्रार्थी बैंक द्वारा प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र सही पेश न करने एवं समस्त अप्रार्थीगण की सही रूप से तामील न होने के कारण और माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत में दिये गये मार्गदर्शन को ध्यान रखते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के विपरीत जाकर प्रार्थी बैंक का धारा 14 का प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रार्थी बैंक का उक्त प्रार्थना खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना करते हुए धारा 13(2) के नोटिस सपठित नियम 3 की पालना करते हुए ऋणी के दस्तावेजों के अनुसार सम्पूर्ण कार्यवाही नये सिरे से करते हुए पुनः धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशदीप)

जिला मजिस्ट्रेट  
श्री बंशानन्द